03/05/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. पीओके घाटी में चीनी सड़क निर्माण का विरोध किया (GS PAPER II: आईआर)
2. बंगाल के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है (GS PAPER II: राजनीति)
3. अध्ययन में पाया गया कि विदेशी पौधों को हटाने से जंगली जानवरों के लिए भोजन सुनिश्चित होगा (GS PAPER III: पर्यावरण)
4. मानक आवश्यक पेटेंट पर न्यायपालिका की छाया (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था, एस एंड टी)
5. टिप बिंदु
6. 'इस छुट्टी' को एक महिला के अधिकार के रूप में मान्यता दें (GS PAPER I: सोसायटी)
7. क्या PMJAY के डिज़ाइन में बदलाव की ज़रूरत है? (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)
8. भारतीय मसालों पर संकट क्यों मंडरा रहा है? (GS PAPER III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
9. अप्रैल पीएमआई ने विनिर्माण क्षेत्र में 42 महीनों में दूसरी सर्वश्रेष्ठ वृद्धि का संकेत दिया (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था)

PatriotICIAS

पीओके घाटी में चीनी सड़क निर्माण का विरोध किया (3 मई) (GS PAPER II: आईआर)

- भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की शक्सगाम घाटी में चीन की कार्रवाई पर विरोध जताया है।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ब्रीफिंग के दौरान इस मुद्दे पर बात की।
- भारत शक्सगाम घाटी को अपना हिस्सा मानता है और 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को अस्वीकार करता है।
- हाल के उपग्रह चित्रों से पता चला है कि निचली शक्सगाम घाटी में चीनी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी पुष्टि आधिकारिक सूत्रों ने भी की है।
- भारत-चीन युद्ध के एक साल बाद 1963 में पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी चीन को सौंप दी थी।
- शक्सगाम घाटी के पास स्थित सियाचिन ग्लेशियर चीन और पाकिस्तान के बीच स्थित भारतीय क्षेत्र है।
- भारत सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को महत्वपूर्ण मानता है, खासकर पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 के गतिरोध के बाद।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के निर्माण और तैनाती से देपसांग और दौलत बेग ओल्डी जैसे क्षेत्रों में भारतीय चौकियों के लिए खतरा पैदा हो गया है।

बंगाल के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है (3 मई) (GS PAPER II: आईआर: केंद्र -राज्य संबंध)

- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की उस शिकायत पर प्रतिक्रिया दी जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने के अधिकार का दावा किया गया था।

Patriotic

- दो न्यायाधीशों वाली पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा की गई डकैती और सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए अपराधों जैसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला।
- पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के एकतरफा दृष्टिकोण और संभावित नतीजों पर चिंता व्यक्त की तथा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शामिल करने की रणनीति का सुझाव दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अंकित तिवारी से संबंधित एक ऐसे ही मामले पर विचार कर रही है, जहां सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने आपराधिक मुकदमा चलाया था।
- पश्चिम बंगाल ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ एक मूल मुकदमा दायर किया, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत सीबीआई जांच का आरोप लगाया गया।
- पश्चिम बंगाल ने दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिए दी गई पूर्व सहमति वापस ले ली।
- केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि राज्य का मूल वाद विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 131 के तहत सीबीआई 'राज्य' नहीं है और उसे इस मुकदमे में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता।

विदेशी पौधों को हटाने से जंगली जानवरों के लिए भोजन सुनिश्चित होगा, अध्ययन में पाया गया (3 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)

- केरल राज्य वन सुरक्षा कर्मचारी संगठन (केएसएफपीएसओ) के एक अध्ययन से पता चलता है कि मुन्नार के चिन्नाक्कनाल में वन क्षेत्रों से विदेशी पौधों को हटाने से जंगली हाथियों के लिए भोजन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- अध्ययन में मानव-हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए स्थानीय लोगों और पंचायत अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाली जमीनी वन टीमें शामिल थीं।
- समस्या को हल करने के लिए जंगलों से बबूल मर्नसी (काला मवेशी) और नीलगिरी जैसी विदेशी प्रजातियों को हटाने के महत्व पर जोर दिया ।
- कई वन क्षेत्रों में विदेशी पेड़ों का बोलबाला है, जिससे अन्य पौधों को उगने के लिए कोई जगह नहीं बचती और हाथियों सहित जंगली जानवरों की आवाजाही में बाधा आती है।
- पश्चिमी भारतीय लैन्टाना (कोंगिनी) चिन्नाक्कनाल परिदृश्य में विशेष रूप से समस्या उत्पन्न कर रही है , जो अन्य प्रजातियों के विकास को बाधित कर रही है तथा पशुओं की पहुंच को प्रतिबंधित कर रही है।
- इस क्षेत्र में वर्तमान में 19 जंगली हाथी हैं, जिनमें दो हाथीदांत हाथी और कई बच्चे तथा मादा हाथी शामिल हैं, जिन्हें आवास संबंधी समस्याओं के कारण बंदीगृह में रखा गया है।
- उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ पैनल ने हाथियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए मुन्नार में अनयिरंकल से ओल्ड देवीकुलम तक हाथी गलियारे को फिर से खोलने की सिफारिश की है।

पेटेंट होल्डअप

PatriotIAS

- **परिभाषा:** पेटेंट होल्डअप एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पेटेंट स्वामी, उद्योग मानक अपनाए जाने के बाद, जिसमें उनकी पेटेंट तकनीक शामिल है, मानक निर्धारित होने से पहले बातचीत की तुलना में अधिक रॉयल्टी वसूलने की कोशिश करता है। यह मानक अपनाने वालों के प्रौद्योगिकी में निवेश और विकल्पों पर स्विच करने की उनकी कम क्षमता का लाभ उठाता है।
- **चिंता:** मानक को लागू करने वाली कम्पनियों को "रोका" जा सकता है तथा उन्हें अत्यधिक रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अब पेटेंट प्राप्त प्रौद्योगिकी के आसपास उत्पादों या बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया है।

पेटेंट होल्डअप एक समस्या क्यों है?

- **नवप्रवर्तन को रोकता है:** पेटेंट में देरी, भविष्य में अत्यधिक लाइसेंसिंग मांगों के डर से, कंपनियों को मानक विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने से रोक सकती है।
- **बढ़ी हुई लागत:** अनुचित रूप से उच्च रॉयल्टी से निर्माताओं की लागत बढ़ जाती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
- **अनिश्चितता:** भविष्य की लाइसेंसिंग लागतों के बारे में अनिश्चितता व्यवसाय नियोजन और निवेश निर्णयों को बाधित कर सकती है।

जहां यह सबसे आम है: मानक-आवश्यक पेटेंट (एसईपी)

- **एसईपी:** पेटेंट जो किसी विशेष प्रौद्योगिकी मानक को लागू करने के लिए आवश्यक हैं।
- **उद्योग: यह** विशेष रूप से उन उद्योगों में प्रचलित है जो एसईपी पर अत्यधिक निर्भर हैं, जैसे दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य।

समाधान और दृष्टिकोण

- **FRAND प्रतिबद्धताएँ:** मानक-निर्धारण संगठन (SSO) अक्सर SEP स्वामियों से अपने पेटेंट को निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण (FRAND) शर्तों पर लाइसेंस देने की प्रतिबद्धता की अपेक्षा करते हैं। हालाँकि, "FRAND" की परिभाषा को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं।
- **पूर्व-लाइसेंसिंग वार्ता:** मानक तय होने से पहले रॉयल्टी दरों पर वार्ता को प्रोत्साहित करना।
- **वैकल्पिक लाइसेंसिंग मॉडल:** लाइसेंसिंग को सरल बनाने और देरी की संभावना को कम करने के लिए पेटेंट पूल जैसे मॉडलों की खोज करना।
- **प्रतिस्पर्धा-विरोधी जांच:** प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानून का उपयोग पेटेंट धारकों द्वारा अत्यधिक रॉयल्टी मांगों या अन्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम और इसकी चुनौतियाँ

- **धारा 3(डी):** भारतीय पेटेंट अधिनियम में इस प्रावधान की सराहना फार्मास्यूटिकल पेटेंटों की "सदाबहारता" को रोकने के लिए की गई है, लेकिन सख्त पेटेंट योग्यता मानक निर्धारित करने के लिए इसकी आलोचना भी की गई है।

औषधीय औषधि

- **अनिवार्य लाइसेंसिंग:** भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग (कुछ परिस्थितियों में पेटेंट धारक की सहमति के बिना जेनेरिक उत्पादन की अनुमति) के प्रावधान हैं। नवाचार प्रोत्साहनों के साथ इसे संतुलित करना एक सतत बहस है।
- **प्रवर्तन:** पेटेंट अधिकारों के प्रवर्तन में चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें उल्लंघन और जालसाजी जैसे मुद्दे शामिल हैं।

विदेशी पौधों को हटाने से जंगली जानवरों के लिए भोजन सुनिश्चित होगा, अध्ययन में पाया गया (3 मई) (GS PAPER III:

Patriot IAS

- केरल राज्य वन सुरक्षा कर्मचारी संगठन (केएसएफपीएसओ) के एक अध्ययन से पता चलता है कि मुन्नार के चिन्नाक्कनाल में वन क्षेत्रों से विदेशी पौधों को हटाने से जंगली हाथियों के लिए भोजन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- अध्ययन में मानव-हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए स्थानीय लोगों और पंचायत अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाली जमीनी वन टीमें शामिल थीं।
- समस्या को हल करने के लिए जंगलों से बबूल मर्नसी (काला मवेशी) और नीलगिरी जैसी विदेशी प्रजातियों को हटाने के महत्व पर जोर दिया ।
- कई वन क्षेत्रों में विदेशी पेड़ों का बोलबाला है, जिससे अन्य पौधों को उगने के लिए कोई जगह नहीं बचती और हाथियों सहित जंगली जानवरों की आवाजाही में बाधा आती है।
- वेस्ट इंडियन लैंटाना (कोंगिनी) चिन्नक्कनाल परिदृश्य में विशेष रूप से समस्याग्रस्त है , जो अन्य प्रजातियों के विकास को रोकता है और जानवरों की पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
- इस क्षेत्र में वर्तमान में 19 जंगली हाथियों की मेजबानी की जाती है, जिनमें दो हाथी और कई बछड़े और मादा हाथी शामिल हैं, जिन्हें निवास स्थान के मुद्दों के कारण कारावास का सामना करना पड़ता है।

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ पैनल ने हाथियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए अनायिरंकल से मुन्नार में पुराने देवीकुलम तक हाथी गलियारे को फिर से खोलने की सिफारिश की है।

पेटेंट पर न्यायपालिका की छाया (3 मई) (GS PAPER III: विनिर्माण क्षेत्र, एस एंड टी)

इससे पहले कि न्यायपालिका भारत के विनिर्माण सपनों को और नुकसान पहुंचाए, सरकार को मानक आवश्यक पेटेंटों को विनियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए।

सीडीएमए (कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस)

- **प्रौद्योगिकी:** **स्प्रेड स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी** पर आधारित , जहां कई उपयोगकर्ता अपने संकेतों को अलग करने के लिए अद्वितीय कोड का उपयोग करके समान आवृत्ति बैंड साझा करते हैं।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
  - कोड-आधारित सिग्नल पृथक्करण के कारण कॉल की गुणवत्ता और सुरक्षा में वृद्धि।
  - ऐतिहासिक रूप से वेरिज़ोन और स्प्रिंट (अमेरिका में) जैसे वाहकों द्वारा पेश किए गए नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है।
- **स्थिति:** हालांकि अभी भी कुछ पुराने नेटवर्कों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सीडीएमए को मुख्य रूप से 2जी और 3जी प्रौद्योगिकी माना जाता है तथा इसे बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है, क्योंकि वाहक कंपनियां 4जी और 5जी प्रौद्योगिकियों में अपग्रेड कर रही हैं।

जीएसएम (मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली)

- **प्रौद्योगिकी:** **टीडीएमए (टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस)** पर आधारित , जहां **उपयोगकर्ता समान आवृत्ति साझा करते हैं लेकिन ट्रांसमिशन के लिए उन्हें अलग-अलग टाइमस्लॉट दिए जाते हैं** ।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
  - व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता, विशेषकर यूरोप में।
  - उपकरणों के बीच आसान विनिमेयता के लिए सिम (सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल) कार्ड का उपयोग।
  - 2जी और प्रारंभिक 3जी नेटवर्क के लिए आधार।
- **स्थिति:** सीडीएमए की तरह, जीएसएम एक विरासती तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। कई पुराने फ़ोन GSM नेटवर्क का समर्थन करते थे, लेकिन इसे तेजी से LTE और 5G द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

एलटीई (दीर्घकालिक विकास)

- **प्रौद्योगिकी:** कुशल डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएफडीएमए (ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस) और एससी-एफडीएमए (सिंगल-कैरियर एफडीएमए) का उपयोग करके एक वास्तविक 4जी तकनीक के रूप में डिजाइन किया गया है।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
  - सीडीएमए और जीएसएम की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च गति और कम विलंबता (प्रतिक्रिया समय)।
  - बेहतर आवाज की गुणवत्ता के लिए वॉयस ओवर एलटीई (वीओएलटीई) का समर्थन।
  - दुनिया भर में आधुनिक 4जी नेटवर्क की रीढ़।
- **स्थिति:** एलटीई विश्व स्तर पर प्रमुख सेलुलर तकनीक है। जबकि 5जी में अपग्रेड जारी है, एलटीई बुनियादी ढांचे का केंद्र बना हुआ है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

PathfinderIAS

महत्वपूर्ण लेख:

- **बदलता परिदृश्य:** आज अधिकांश फोन एलटीई और 5जी अनुकूलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे स्टैंडअलोन सीडीएमए और जीएसएम क्षमताएं कम आम हो गई हैं।
- **वाहक अंतर:** अतीत में विशिष्ट CDMA/GSM वाहक नेटवर्क धीरे-धीरे LTE की ओर स्थानांतरित हो गए, जिससे कभी-कभी उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन के विकल्प पर भी असर पड़ा।

- **'मानक आवश्यक पेटेंट' (एसईपी)** के उपयोग के संबंध में संभावित संकट का सामना कर रहा है।
- ये पेटेंट दूरसंचार जैसे उद्योगों द्वारा "मानकों" के रूप में अपनाई गई प्रौद्योगिकियों को कवर करते हैं।
- ऐसे मानकों के उदाहरणों में दूरसंचार क्षेत्र में सीडीएमए, जीएसएम और एलटीई शामिल हैं।
- मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न ब्रांड के सेल्युलर फोन एक साथ काम कर सकें।
- उदाहरण के लिए, जब GSM मानक बन गया, तो सभी फोन निर्माताओं को अपने हैंडसेट को GSM के अनुकूल बनाना पड़ा।
- यह मुद्दा सेलुलर फोन के लिए घरेलू विनिर्माण उद्योग बनाने के भारत के प्रयासों को प्रभावित करता है।
- एसईपी का विनियमन काफी हद तक न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्होंने समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं किया है।

अपारदर्शी मॉडल

- **प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानकों का निर्धारण " मानक सेटिंग संगठनों" (एसएसओ) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो ज्यादातर निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा संचालित होते हैं।**
- दूरसंचार में सीमित नवाचार वाले भारत जैसे देशों का इस बात पर बहुत कम प्रभाव है कि मानक कैसे निर्धारित किए जाते हैं या एसईपी को कैसे लाइसेंस दिया जाता है।
- एसईपी रखने वाली कंपनियों को बहुत लाभ होता है क्योंकि प्रत्येक सेल फोन निर्माता को प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन मानकों का लाइसेंस लेना होगा।
- **विकल्पों की कमी एसईपी मालिकों को उच्च रॉयल्टी की मांग करने की अनुमति देती है, जिससे "पेटेंट होल्डअप" समस्या पैदा होती है।**
- एसएसओ का लक्ष्य एसईपी मालिकों को उचित, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण (एफआरएएनडी) दरों पर प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस देने की आवश्यकता के द्वारा इसे रोकना है।
- हालाँकि, प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा स्व-नियमन अपारदर्शी और अप्रभावी रहा है, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए रिकॉर्ड जुर्माने लगाए गए हैं।
- एसईपी की प्रमुख कंपनी क्वालकॉम को चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यूरोपीय आयोग से अरबों डॉलर का जुर्माना झेलना पड़ा है।
- यद्यपि अपील पर सभी जुर्मानों को बरकरार नहीं रखा गया है, फिर भी वे दर्शाते हैं कि अन्य देश प्रतिस्पर्धा कानून के नजरिए से इस मुद्दे को किस प्रकार संबोधित करते हैं।

न्यायिक सुस्ती और सक्रियता का प्रभाव

- एसईपी लाइसेंसिंग के मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया न्यायिक सुस्ती और दिल्ली उच्च न्यायालय की सक्रियता दोनों से चिह्नित रही है।
- **2013 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने माइक्रोमैक्स की शिकायत के आधार पर एरिक्सन द्वारा अपने SEP के लिए उच्च रॉयल्टी की मांग करके अपने प्रभुत्व की स्थिति का कथित दुरुपयोग करने की जांच शुरू की।**
- एरिक्सन ने सीसीआई के जांच के अधिकार को चुनौती दी और तर्क दिया कि केवल पेटेंट कार्यालय के पास ही पेटेंट के दुरुपयोग से निपटने का अधिकार है।

PathfinderIAS

- प्रारंभ में, 2016 में एकल न्यायाधीश ने सीसीआई के पक्ष में फैसला सुनाया , लेकिन एरिक्सन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की, जिसके परिणामस्वरूप सात साल तक लंबी कानूनी लड़ाई चली।
- डिवीजन बेंच ने अंततः जुलाई 2023 में सीसीआई के खिलाफ फैसला सुनाया, जिससे सीसीआई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे भारत एसईपी लाइसेंसिंग प्रथाओं की जांच के बिना एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।
- इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एरिक्सन सहित एसईपी मालिकों द्वारा सेल फोन निर्माताओं के खिलाफ कथित पेटेंट उल्लंघन और क्षतिपूर्ति के लिए दायर मुकदमों पर कार्यवाही शुरू कर दी।
- आदर्शतः इन मुकदमों को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए था जब तक प्रतिस्पर्धा कानून के मुद्दे हल नहीं हो जाते।
- आमतौर पर, **इस तरह के मुकदमे में पेटेंट वैधता, उल्लंघन और क्षति पर परीक्षण शामिल होता है, जो जटिल और समय लेने वाला हो सकता है।**
- उदाहरण के लिए , **एरिक्सन द्वारा लावा इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा** निर्णय लेने में आठ साल लग गए, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित बंसल ने 500 पन्नों का फैसला सुनाया।
- दिल्ली **उच्च न्यायालय पेटेंट उल्लंघन के मामलों में अंतरिम राहत दे रहा है, जिससे निर्माताओं को परीक्षण के दौरान अदालत में पैसा जमा करने की आवश्यकता होती है।**
- ये जमा आदेश, जिनमें अक्सर बड़ी रकम शामिल होती है, वाणिज्यिक कानून में अभूतपूर्व हैं और प्रतिवादियों, मुख्य रूप से भारतीय कंपनियों को **कार्यशील पूंजी से वंचित करते हैं ।**
- अदालत जनहित याचिका में इस्तेमाल किए गए तर्कों के समान, "न्याय करने की अपनी अंतर्निहित शक्तियों" का इस्तेमाल करके इस कार्रवाई को उचित ठहराती है।
- हालाँकि, यह दृष्टिकोण प्रतिवादियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को रोक सकता है।
- जबकि सरकार "उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन" जैसी योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, पेटेंट मामलों में न्यायिक सक्रियता निष्पक्षता और निवेश आकर्षण के बारे में चिंता पैदा करती है।
- **भारत में नौकरियाँ पैदा करने वाले निर्माताओं के विपरीत, एसईपी मालिकों को देश से पैसा बाहर ले जाने के रूप में देखा जाता है, जो निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुचित प्रथाओं से बचाने के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है।**

यूरोप का मामला

- भारत सरकार को भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को नुकसान से बचाने के लिए एसईपी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने और नियमों को लागू करने की आवश्यकता है।
- एसईपी को विनियमित करने के लिए यूरोपीय संसद द्वारा इसी तरह के नियामक उपाय लागू किए गए हैं।
- भारत के पास ऐसे नियमों को लागू करने के लिए एक मजबूत मामला है, क्योंकि इसमें एसएसओ द्वारा एसईपी चयन पर प्रभाव का अभाव है और विदेशी तकनीकी कंपनियों के पेटेंट को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा बाध्य है।

महत्वपूर्ण बिंदु: जीएसटी और सुधारों पर (3 मई)

Patriot IAS

मजबूत जीएसटी राजस्व के साथ, अगली सरकार को महत्वपूर्ण सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए

- अप्रैल में, **जीएसटी राजस्व ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो गया** पहली बार के लिए।
- अप्रैल में आम तौर पर मार्च में गतिविधि के कारण उच्च जीएसटी संग्रह देखा जाता है, जब करदाता अपनी पुस्तकों को अंतिम रूप देते हैं और कर दाखिल करने की समय सीमा को पूरा करते हैं।
- पिछले महीने का सकल जीएसटी राजस्व ₹2.1 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक था, जो अप्रैल 2023 से 12.4% अधिक है।
- यह अनिश्चित है कि क्या 2 लाख करोड़ रुपये का नया सामान्य मासिक संग्रह बन जाएगा, क्योंकि आगामी महीनों में इसमें कमी देखी जा सकती है।
- हालाँकि, यदि अर्थव्यवस्था गति बनाए रखती है और जीएसटी राजस्व वृद्धि 11% -12% पर जारी रहती है, तो पिछले अप्रैल का ₹1.87 लाख करोड़ का संग्रह इस वर्ष का मासिक औसत हो सकता है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसका श्रेय मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल संग्रह को दिया।
- **फर्जी बिलिंग जैसे धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई और सख्त अनुपालन मानदंडों ने राजस्व वृद्धि में योगदान दिया है।**
- 2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब 10% से कम वृद्धि की आवश्यकता है, जबकि CGST राजस्व पिछले वर्ष के लक्ष्य से अधिक है।
- अगली सरकार का ध्यान **जीएसटी के दायरे को बढ़ाने और जटिल दर संरचना को सरल बनाने पर होना चाहिए।**
- सुधारों में विसंगतियों को दूर करना, उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए कर को सरल बनाना और विकास को बढ़ावा देना प्राथमिकता होनी चाहिए।
- भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणापत्रों में जीएसटी से संबंधित वादों को रेखांकित किया है, जिसमें स्मार्ट जीएसटी सुधारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

पूर्वी मोर्चा: पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई पर (3 मई)

पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण वाम दलों और कांग्रेस को किनारे कर रहा है

- 2019 में 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में अपना प्रदर्शन बेहतर करना है।
- इसके बावजूद, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 2021 विधानसभा चुनाव में 77 सीटों और 38.1% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की।
- वर्तमान आम चुनाव में, मतदान सभी सात चरणों में होता है, और भाजपा को अन्य जगहों पर संभावित नुकसान की भरपाई के लिए अपनी सीटें बढ़ाने की उम्मीद है।
- **भाजपा टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार, जमीन पर कब्जा, यौन उत्पीड़न और स्कूल भर्ती घोटाले के आरोपों को उजागर कर रही है।**
- कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लगभग 25,000 शिक्षक नियुक्तियों को रद्द करने को भाजपा के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।

Patriotic IAS

- टीएमसी का अभियान **नई दिल्ली द्वारा धन रोकने, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और लक्ष्मीर जैसी नकद हस्तांतरण योजनाओं पर केंद्रित है। महिलाओं के लिए भंडार .**
- भाजपा महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर देती है और संदेशखाली में एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारती है , जहां महिलाओं पर हमले की सूचना मिली थी।
- भाजपा को उत्तर बंगाल में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जबकि टीएमसी दक्षिण में मुस्लिम मतदाताओं के उच्च अनुपात वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- वाम-कांग्रेस गठबंधन अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कुछ सीटों को प्रभावित कर सकता है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के हटने से टीएमसी को फायदा होगा।
- भाजपा **राम मंदिर, रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और बांग्लादेश के साथ अवैध सीमा पार जैसे विषयों को उठाती है** ।
- धार्मिक ध्रुवीकरण ने पिछले चुनावों में भूमिका निभाई, 2019 में भाजपा और 2021 में तृणमूल के पक्ष में , वामपंथियों और कांग्रेस को किनारे कर दिया।
- तृणमूल बंगाली पहचान पर जोर देती है और भाजपा को राज्य के हितों के प्रति असंवेदनशील बताती है, जबकि भाजपा पश्चिम बंगाल को हिंदू राजनीति में ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसर के रूप में देखती है।

क्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के डिज़ाइन में बदलाव की ज़रूरत है? (3 मई) (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)

पीएमजेएवाई

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)।

- **लॉन्च:** 23 सितंबर, 2018.
- **नेचर:** दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना, जो भारत की सबसे कमजोर आबादी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
- **प्रशासित :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)

प्रमुख विशेषताऐं

- **लाभार्थी:** सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों के आधार पर 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ व्यक्ति) पात्र हैं।
- **कवरेज:** प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये (लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर) तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- **अस्पताल में भर्ती होने का खर्च:** पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती को कवर करता है।
- **कैशलेस उपचार:** लाभार्थियों को नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिलता है, जिसके लिए अपनी जेब से भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।
- **पोर्टेबिलिटी:** लाभ पूरे देश में उपलब्ध हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों और राज्यों के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित होती है।

पात्रता की जांच कैसे करें और आवेदन कैसे करें

1. **PMJAY वेबसाइट:** आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2. **क्या मैं पात्र हूं?:** पात्रता की जांच करने के लिए "क्या मैं पात्र हूं" अनुभाग का उपयोग करें।

PatrioticIAS

3. **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** पात्रता की जांच करने और ई-कार्ड बनाने में सहायता के लिए अपना निकटतम सीएससी ढूंढें।

अस्पताल में भर्ती होने से परे लाभ

- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र:** पीएमजेएवाई स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को उन्नत करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत है।
- **कवरेज का विस्तार:** योजना कवरेज बढ़ाने के लिए लगातार नए लाभार्थी परिवारों की पहचान करती है।

PatrioticIAS

- आयुष्मान भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए 2018 में शुरू किया गया एक सरकारी कार्यक्रम है।
- इसके दो भाग हैं: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र , और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)।
- PMJAY का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक कम आय वाले परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है।
- PMJAY ने 34.27 करोड़ कार्ड जारी किए हैं और 30,000 से अधिक अस्पतालों में लगभग 6.5 करोड़ लोगों का इलाज किया है।
- कुछ राज्यों में कुछ अस्पतालों ने बकाया राशि का भुगतान न किए जाने की बात कही है, जिसके कारण उन्हें या तो पीएमजेएवाई के मरीजों को वापस करना पड़ रहा है या कम संख्या में मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है।
- इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या इन मुद्दों के समाधान के लिए पीएमजेएवाई में बदलाव की आवश्यकता है।
- अवनि कपूर और नचिकेत मोर ने जुबेदा हामिद द्वारा संचालित एक बातचीत में इस विषय पर चर्चा की।

क्या पीएमजेएवाई को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए इसके डिजाइन में बदलाव की आवश्यकता है?

- **नचिकेत मोर** : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और इसके उद्देश्य पर चर्चा की गई।
- पीएमजेएवाई को सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा की कमियों को दूर करने और मरीजों को निजी क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- हालाँकि, PMJAY वर्तमान में कुल स्वास्थ्य व्यय का केवल 2.5% ही कवर करता है, जो दर्शाता है कि इसे व्यापक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
- शोध से पता चलता है कि कई राज्यों में सरकारी विभागीय व्यय को पीएमजेएवाई व्यय के साथ मिलाना दवाओं और निदान सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए पर्याप्त हो सकता है।
- वित्त पोषण के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र, विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों में, प्राथमिक देखभाल के अपर्याप्त उपयोग और अकुशलता के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में संघर्ष करता है।
- अस्पताल-केंद्रित डिजाइन के ऊपर पीएमजेएवाई जैसी योजनाएं लागू करने से सरकारी संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है और निम्न आय वाले परिवारों के लिए बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- मोर ने पीएमजेएवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है ताकि उनकी जेब से होने वाले खर्च को खत्म किया जा सके।
- उन्होंने स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए संगठित, उच्च गुणवत्ता वाले तरीके से देखभाल खरीदने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएचए) की भूमिका पर जोर दिया।
- **अवनि कपूर** : पीएमजेएवाई में स्वास्थ्य सेवा की मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- पैनल में शामिल अस्पतालों में से 43% निजी हैं, शेष सरकारी हैं।
- लोग अक्सर बेहतर सेवाओं के कारण सार्वजनिक अस्पतालों की अपेक्षा निजी अस्पतालों को चुनते हैं।
- निजी क्षेत्र क्षमता संबंधी समस्याओं, भुगतान में देरी, दावों की अस्वीकृति तथा शुल्क की अधिकतम सीमा के कारण मरीजों को वापस भेज सकता है।
- पीएमजेएवाई की सफलता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरीज निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं या सार्वजनिक अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते हैं।

पीएमजेएवाई के अंतर्गत राज्यों के बीच प्रदर्शन असमानता कितनी व्यापक है?

- **अवनि कपूर** : कुछ क्षेत्रों में अस्पताल की उपलब्धता और गतिविधि से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।
- सूचीबद्ध होने के बाद से निष्क्रिय हैं ।
- पिछले छह महीनों में उत्तर प्रदेश में केवल 50% सूचीबद्ध अस्पताल ही सक्रिय रहे हैं।
- विभिन्न राज्यों में कवरेज अलग-अलग है, कुछ राज्यों में कवरेज अन्य की तुलना में कम है।
- राज्यों के भीतर अस्पतालों का वितरण विषम है।
- शासन प्रक्रियाएं पीएमजेएवाई कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
- कुछ राज्यों में दावा भुगतान में 45 दिनों से अधिक की देरी होती है।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दावों का संकेन्द्रण है।
- विशिष्ट राज्यों में दावों के संकेन्द्रण के पीछे के कारणों को समझने के लिए आगे अनुसंधान की आवश्यकता है।
- **नचिकेत मोर** : इस बात पर जोर दिया गया है कि भुगतान में देरी राज्यों की संपत्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि अस्पतालों की क्षमता से संबंधित है।

PatriotIAS

- उन्होंने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का उदाहरण दिया, जहां अस्पतालों की क्षमता अपर्याप्त है, जिसके कारण भुगतान में देरी होती है।
- मोर ने बीमा योजनाओं में नेटवर्क की पर्याप्तता के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसका अर्थ है कि लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को अस्पताल नजदीक में होना चाहिए।
- कई अन्य देशों के विपरीत, भारत में अस्पतालों की निकटता सुनिश्चित किए बिना बीमा योजनाएं प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- यह कमी भारत के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से स्पष्ट है।
- मोर का सुझाव है कि सार्वजनिक क्षेत्र को उन क्षेत्रों में अस्पताल के बुनियादी ढांचे के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, जहां निजी क्षेत्र के निवेश की संभावना नहीं है, जैसे बस्तर।

स्वास्थ्य के लिए भारत का अपनी जेब से खर्च कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी 47-50% के आसपास है, जो वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। क्या हमें ऐसी प्रणाली पर ध्यान देने की ज़रूरत है जहां बाह्य रोगी देखभाल, निदान और दवाओं को भी कवर किया जा सके?

- **नचिकेत मोर** : स्वास्थ्य देखभाल में सरकारी प्रयासों के साथ पीएमजेएवाई और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की तुलना करने के खिलाफ तर्क देता है।
- वह इस बात पर जोर देते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल व्यय का अधिकांश हिस्सा राज्य और केंद्र स्तर पर सरकारी खर्च से आता है, जो पीएमजेएवाई और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की फंडिंग से कहीं अधिक है।
- मोर बताते हैं कि ये योजनाएं मुख्य रूप से बाह्य रोगी (ओपी) देखभाल पर केंद्रित हैं, जिसमें व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दवाओं और ओपी देखभाल के लिए आवंटित किया गया है।
- वह सवाल करते हैं कि क्या दुनिया भर में किसी भी सरकार के पास अतिरिक्त बीमा परत के साथ एक अलग सार्वजनिक-वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विखंडन हो सकता है।
- मोर अपनी जेब से खर्च के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस विखंडन को संबोधित करने का सुझाव देते हैं।
- **अवनि कपूर** : इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पीएमजेएवाई का मौजूदा मॉडल अपनी वित्तीय बाधाओं को देखते हुए सभी स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को कवर करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- उन्होंने उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु और राजस्थान का हवाला देते हुए मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने में विभिन्न राज्य योजनाओं की प्रभावशीलता का उल्लेख किया।
- स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जेब से खर्च करने के मामले में भारत 189 देशों में से 67वें स्थान पर है, जो व्यापक कवरेज की आवश्यकता को दर्शाता है।
- केंद्र सरकार को पीएमजेएवाई निधि का 60% आवंटित करना है, लेकिन वास्तविक खर्च इस लक्ष्य से कम है।
- पीएमजेएवाई को स्वास्थ्य देखभाल लागत संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था, विशेष रूप से इनपेशेंट उपचार के लिए, जो कि आउटपेशेंट उपचार की तुलना में महंगा हो सकता है।
- कपूर ने पीएमजेएवाई को अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक समग्र प्रणाली के रूप में विचार करने के महत्व पर जोर दिया।

PatriotIAS

सरकार ने कहा कि यह यूएचसी प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। क्या आप यह तर्क देंगे कि यूएचसी प्राप्त करने की दिशा में भारत के लिए बीमा मॉडल सही नहीं है? क्या कोई अन्य देश बीमा मॉडल के माध्यम से इसे प्राप्त करने में सक्षम रहा है?

- **नचिकेत मोर** सुझाव है कि बीमा मॉडल, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से निधियों को अलग करता है और प्रदर्शन को पुरस्कृत करता है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रदर्शन में काफी सुधार कर सकता है, विशेष रूप से गरीब राज्यों में।
- उनका मानना है कि यह बीमा मॉडल थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम और उरुग्वे जैसे देशों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्रदान करने में सफल रहा है।
- मोर संकेत देते हैं कि भारत का वर्तमान स्वास्थ्य सेवा मॉडल अब प्रभावी नहीं रहा, और उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएचए) के माध्यम से बीमा-आधारित दृष्टिकोण को लागू करने में संभावनाएं नजर आती हैं।
- उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बीमा दृष्टिकोण आवश्यक रूप से पारंपरिक क्षतिपूर्ति मॉडल का अनुसरण नहीं करेगा, जहां प्रतिपूर्ति के लिए दावे दायर किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे तरीकों से स्वास्थ्य देखभाल की कीमतें बढ़ सकती हैं।
- मोर क्रेता-प्रदाता विभाजन के महत्व पर प्रकाश डालता है, जहां स्वास्थ्य देखभाल निधि को सेवा वितरण से अलग किया जाता है, इसे आगे बढ़ने के लिए एक व्यवहार्य मार्ग के रूप में सुझाया गया है।
- **अवनि कपूर** : नचिकेत मोर के आकलन से सहमत हैं।
- वह अपने वर्तमान डिज़ाइन में बीमा मॉडल की प्रभावशीलता के बारे में संदेह व्यक्त करती है।
- कपूर निम्न और मध्यम आय वाले देशों और स्वास्थ्य बीमा पर एक हालिया पेपर का संदर्भ देते हैं।
- पेपर सुझाव देता है कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि सरकारी सब्सिडी कैसे प्रसारित की जाती है , बल्कि विशिष्ट भुगतान संरचनाओं और गैर-मूल्य तंत्रों को लागू करने के बारे में भी है।
- कपूर का मानना है कि पीएमजेएवाई, अपने वर्तमान स्वरूप में, तब तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर अधिक ध्यान न दिया जाए।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) (GS PAPER III: अर्थव्यवस्था)

- **आर्थिक संकेतक**: पीएमआई एक समग्र संकेतक है जो **किसी देश के विनिर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य को मापता है।** यह **क्रय प्रबंधकों के बीच किये गए सर्वेक्षणों पर आधारित है** विनिर्माण कंपनियों में.
- पीएमआई में पांच उप-सूचकांक शामिल हैं:
    - नए आदेश
    - उत्पादन स्तर
    - रोज़गार
    - आपूर्तिकर्ता डिलीवरी
    - सूची

- **व्याख्या:**

    - पीएमआई का 50 से ऊपर रहना विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार का संकेत है।
    - पीएमआई का 50 से नीचे रहना इस क्षेत्र में संकुचन का संकेत है।

PathmicIAS

- पीएमआई = 50 कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है।

- समग्र आर्थिक गतिविधि के अग्रणी सूचक के रूप में अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं द्वारा पीएमआई का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: एथिलीन ऑक्साइड (EtO) का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? (ए) निर्माण और बुनियादी ढांचा (बी) स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरण (सी) वस्त्र निर्माण (डी) सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास	उत्तर: (बी) स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरण **व्याख्या** : सूक्ष्मजीवों को मारने में इसकी प्रभावशीलता के कारण EtO का पारंपरिक प्राथमिक उपयोग चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों का रोगाणुनाशन रहा है।
प्रश्न 2: एथिलीन ऑक्साइड (EtO) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? (ए) यह फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है गंध वाली अत्यधिक ज्वलनशील गैस है (सी) इसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है (डी) इसे थोड़ी मात्रा में मानव उपभोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है।	उत्तर: (सी) इसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है **स्पष्टीकरण:** इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) और अन्य स्वास्थ्य संगठन ईटीओ को एक ज्ञात मानव कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है।
प्रश्न 3: खाद्य उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) के उपयोग के बारे में हालिया चिंताएँ मुख्य रूप से निम्न से उत्पन्न होती हैं: (ए) खाद्य पदार्थों के स्वाद और पोषण मूल्य पर इसका प्रभाव (बी) कुछ व्यक्तियों में एलर्जी प्रतिक्रियाओं का खतरा (सी) जोखिम से जुड़े संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम (डी) इसके उत्सर्जन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति	उत्तर: (सी) जोखिम से जुड़े संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम **स्पष्टीकरण:** खाद्य पदार्थों में EtO के संबंध में प्राथमिक चिंता यह है कि दीर्घकालिक संपर्क, यहां तक कि निम्न स्तर पर भी, कुछ कैंसरों के जोखिम को बढ़ा सकता है।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आयातित खाद्य उत्पादों को जीवाणुरहित करने के लिए EtO के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? (ए) चीन (बी) यूरोपीय संघ (सी) ब्राज़ील (डी) ऑस्ट्रेलिया	उत्तर: (बी) यूरोपीय संघ **स्पष्टीकरण:** यूरोपीय संघ ने खाद्य पदार्थों में ईटीओ अवशेषों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, तथा आयातित खाद्य उत्पादों के लिए स्टरलाइज़ेशन विधि के रूप में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति "पेटेंट होल्डअप" समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? (ए) कोई कंपनी किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धियों को अपनी पेटेंट प्रौद्योगिकी का लाइसेंस देने से इनकार कर देती है।	उत्तर : (बी) एक कंपनी अपने मानक-आवश्यक पेटेंट का उपयोग करने की इच्छुक अन्य कंपनियों से अत्यधिक रॉयल्टी की मांग करती है। **स्पष्टीकरण:** पेटेंट होल्डअप एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है, जहां एक कंपनी के पास ऐसे पेटेंट

PatriotIAS

(बी) एक कंपनी अपने मानक-आवश्यक पेटेंट का उपयोग करने की इच्छुक अन्य कंपनियों से अत्यधिक रॉयल्टी की मांग करती है। (सी) एक कंपनी किसी अन्य कंपनी पर पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा करती है, भले ही उल्लंघन का दावा कमजोर हो। (डी) एक कंपनी एक नया उत्पाद विकसित करती है जो पहले से पेटेंट किए गए आविष्कार में महत्वपूर्ण सुधार करता है।	होते हैं जो किसी प्रौद्योगिकी मानक (जैसे, 5G घटक) के लिए आवश्यक होते हैं, जो मानक के कार्यान्वयनकर्ताओं से अनुचित रूप से उच्च रॉयल्टी की मांग करके उस स्थिति का फायदा उठाती है।
प्रश्न 6: पेटेंट होल्डअप निम्नलिखित के विकास और कार्यान्वयन में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है: (ए) फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण (बी) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (सी) दूरसंचार प्रौद्योगिकियां (डी) हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियां	उत्तर: (सी) दूरसंचार प्रौद्योगिकियां **स्पष्टीकरण:** पेटेंट होल्डअप विशेष रूप से जटिल तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित है, जहां कई कंपनियां दूरसंचार जैसे उद्योग मानकों में योगदान देती हैं। 4जी या 5जी जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए कई आवश्यक पेटेंट शामिल हैं, यदि लाइसेंसिंग पर निष्पक्ष रूप से बातचीत नहीं की जाती है तो होल्डअप के अवसर पैदा होते हैं।
प्रश्न 7: पेटेंट होल्डअप की समस्या के समाधान के लिए, FRAND लाइसेंसिंग शर्तों की अवधारणा की अक्सर वकालत की जाती है। "फ्रेंड" का क्या मतलब है? (ए) निष्पक्ष, पारस्परिक और गैर-भेदभावपूर्ण (बी) लचीला, उचित और विस्तार से बातचीत (सी) निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण (डी) निश्चित दर, पारस्परिक और गैर-प्रकटीकरण	उत्तर: (सी) उचित, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण **स्पष्टीकरण:** FRAND का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानक-आवश्यक पेटेंट (SEP) के स्वामी उन पेटेंटों को ऐसी शर्तों पर लाइसेंस दें जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए उचित हों।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय/संगठन अक्सर पेटेंट होल्डअप मुद्दों से संबंधित विवादों को सुलझाने में भूमिका निभाता है? (ए) प्रतिस्पर्धा आयोग और अविश्वास प्राधिकरण (बी) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) (सी) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) (डी) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)	उत्तर: (ए) प्रतिस्पर्धा आयोग और अविश्वास प्राधिकरण **स्पष्टीकरण:** पेटेंट होल्डअप मुद्दे कभी-कभी प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ पैदा कर सकते हैं जब कंपनियाँ SEPs के साथ अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करती हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग और एंटीट्रस्ट विनियामक ऐसे मामलों की जाँच करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन पेटेंट अधिनियम के तहत भारत में पेटेंट संरक्षण के लिए पात्र नहीं है? (ए) एक नया फार्मास्युटिकल यौगिक (बी) आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज किस्म (सी) एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम (डी) एक गणितीय खोज	उत्तर: (डी) एक गणितीय खोज **स्पष्टीकरण:** गणितीय खोजें, प्रकृति के नियम और अमूर्त विचार आम तौर पर पेटेंट योग्य नहीं होते क्योंकि उन्हें मौलिक ज्ञान माना जाता है। अन्य विकल्प संभावित रूप से पेटेंट योग्य हो सकते हैं यदि वे नवीनता, आविष्कारशीलता और औद्योगिक प्रयोज्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं।
प्रश्न 10: भारत में पेटेंट की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? (ए) 10 वर्ष (बी) 15 वर्ष (सी) 20 वर्ष (डी) अनिश्चित	उत्तर : (सी) 20 वर्ष **स्पष्टीकरण:** पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधनों के साथ) पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष की पेटेंट सुरक्षा अवधि प्रदान करता है।

प्रश्न 11: भारत में पेटेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पेटेंट धारक को किसी आविष्कार को बनाने, बेचने और उपयोग करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। 2. पेटेंट उस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है जहां आविष्कार विकसित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (ए) केवल 1 **स्पष्टीकरण:** कथन 1 सही है. पेटेंट धारक को आविष्कार पर समय-सीमित एकाधिकार प्रदान करते हैं। कथन 2 गलत है. भारत में पेटेंट, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से प्रदान किए जाते हैं।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा "प्रोसेस पेटेंट" का उदाहरण है? (ए) मोबाइल फोन के लिए एक अद्वितीय डिजाइन पर एक पेटेंट (बी) दवा निर्माण की एक नई विधि पर पेटेंट (सी) आनुवंशिक रूप से इंजीनियर पौधे पर एक पेटेंट (डी) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर एक पेटेंट	उत्तर: (बी) दवा निर्माण की एक नई विधि पर पेटेंट **स्पष्टीकरण:** प्रक्रिया पेटेंट किसी चीज़ को बनाने के पीछे की विशिष्ट विधि या प्रक्रिया की रक्षा करता है, न कि अंतिम उत्पाद की। अन्य विकल्पों को क्रमशः डिज़ाइन पेटेंट, उत्पाद पेटेंट या कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किए जाने की अधिक संभावना है।
प्रश्न 13: 50 से ऊपर का पीएमआई रीडिंग क्या दर्शाता है? (ए) एक आर्थिक क्षेत्र के भीतर विस्तार (बी) एक आर्थिक क्षेत्र के भीतर संकुचन (सी) किसी आर्थिक क्षेत्र में ठहराव (डी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट	उत्तर : (ए) एक आर्थिक क्षेत्र के भीतर विस्तार **स्पष्टीकरण:** 50 से ऊपर का पीएमआई किसी दिए गए क्षेत्र (विनिर्माण या सेवा) में उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार जैसे संकेतकों में समग्र वृद्धि या विस्तार को इंगित करता है।
प्रश्न 14: पीएमआई की गणना सर्वेक्षण के आधार पर की जाती है: (ए) सरकारी अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद् (बी) प्रासंगिक उद्योगों में वरिष्ठ अधिकारी (सी) शेयर बाजार विश्लेषक (डी) सभी आय समूहों के उपभोक्ता	उत्तर: (बी) प्रासंगिक उद्योगों में वरिष्ठ अधिकारी **स्पष्टीकरण:** पीएमआई विनिर्माण या सेवा क्षेत्र के अधिकारियों (अक्सर क्रय प्रबंधकों) से एकत्र किए गए सर्वेक्षण डेटा पर निर्भर करता है। व्यावसायिक गतिविधि के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएँ सूचकांक की गणना के लिए आधार प्रदान करती हैं।
प्रश्न 15: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? (ए) यह एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है (बी) यह आर्थिक गतिविधि में पूर्वव्यापी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है (सी) इसका उपयोग मुख्य रूप से मुद्रास्फीति पर नज़र रखने के लिए किया जाता है (डी) इसका व्यापक आर्थिक स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है	उत्तर: (ए) यह एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है **स्पष्टीकरण:** पीएमआई को एक प्रमुख संकेतक माना जाता है क्योंकि यह वर्तमान और अपेक्षित स्थितियों के बारे में अधिकारियों का सर्वेक्षण करता है। पीएमआई में बदलाव अक्सर निकट भविष्य में व्यापक आर्थिक रुझानों में बदलाव का संकेत दे सकते हैं।
प्रश्न 16: पीएमआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: पीएमआई डेटा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। पीएमआई निजी संगठनों द्वारा संकलित किया जाता है और सरकारी आंकड़ों से स्वतंत्र होता है।	उत्तर: (सी) 1 और 2 दोनों **स्पष्टीकरण** कथन 1 सही है। PMI डेटा आम तौर पर मासिक रूप से जारी किया जाता है, जो अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।

PatriotICAS

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	कथन 2 सही है। जबकि सरकारें इसका उपयोग कर सकती हैं, PMI को IHS मार्किट जैसी निजी संस्थाओं द्वारा संकलित किया जाता है जो आर्थिक आंकड़ों में विशेषज्ञता रखती हैं।

PatrioticIAS